

**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या <b>035/2020</b> (GCMS 2020/00090)	दायर दिनांक <b>05.11.2020</b>	निर्णय दिनांक <b>18.02.2021</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

**अनवान**

दिलखुश पिता रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

**अपीलान्ट****बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

**रेस्पोंडेंट**

**-:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार. भदेसर बमिसल कमांक 076/2020 तारीख आदेश 22.09.2020 ::-**

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट  
श्री भैरुलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलान्ट  
राजकीय अधिवक्ता

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एव वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का नन्नाणा के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट अतिक्रमी ने मौजा नन्नाणा तहसील भदेसर की चारागाह आराजी नम्बर 1175 पर अतिमक्रमण कर लिया है, जिसके विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जावे। आराजी नम्बर 1178 अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है व उक्त आराजी से लगी हुयी आराजी नम्बर 1175 अवस्थित है, जिस पर अपीलान्ट ने कुंआ व द्युबबेल खुदवा रखा है व उक्त आराजी नम्बर 1175 का अपीलान्ट



चाह के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व अपने खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 1175 जो चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड है व उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कुंआ व ट्युबबेल खुदा हुआ है, जिससे अपीलान्ट राजस्व भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ) कुंए खोदने व पम्प लगाने के लिए भूमि आंवटन ) नियम 1979 के नियम 12 क के अनुसार नियमन कराये जाने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.08.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी 22.09.2020 नियत की गयी। अपीलान्ट दिनांक 22.09.2020 को विचारण न्यायालय में सम्मन की पालना में उपस्थित हुआ व जवाब एवं दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट किस तरह से अतिक्रमी व मौके पर किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, कही स्पष्ट नहीं किया व छपे-छपाये फार्म पर खानापूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.09.2020 की अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.10.2020 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये व कब्जा हटाने की कार्यवाही करने लगे, तो अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी हुयी, तत्पश्चात दिनांक 27.10.2020 को अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। फिर भी अपील ने हुए विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम मय शपथपत्र के अलग से पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश विवादित आराजीयात, पक्षकारानः श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे अवस्थित होने से अपील अपीलान्ट श्रीमान के न्यायालय में पेश है। अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ पेश है। अन्य तथ्य वक्त बहस अर्ज किये जावेगे । अंत में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार पर भी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित



विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 22.09.2020 निरस्त फरमाया जाकर मौजा नन्नाणा की चारागाह आराजी नम्बर 1175 रकबा 0.15 हेक्टर का कुंआ व ट्युबवेल नियमन आदेश पारित फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार भदेसर के पत्रांक/राजस्व/2021/15 दिनांक 05.01.2021 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 076/2020 अनवानी सरकार बनाम दिलखुश पिता रतनलाल जाट निवासी नन्नाणा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 18.02.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया, इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम 1963 सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.09.2020 की अपीलांट को जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.10.2020 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये व कब्जा हटाने की कार्यवाही करने लगे, तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी हुई, तत्पश्चात दिनांक 27.10.2020 को अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। दिनांक 22.09.2020 से दिनांक 20.10.2020 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.09.2020 पर अपीलांट के हस्ताक्षर निशानी अंकित है एवं अपीलांट आदेश दिनांक 22.09.2020 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने



बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया, ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 22.09.2020 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का नन्नाणा के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट अतिक्रमी ने मौजा नन्नाणा तहसील भदेसर की चारागाह आराजी नम्बर 1175 पर अतिमक्रमण कर लिया है, जिसके विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जावे। आराजी नम्बर 1178 अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है व उक्त आराजी से लगी हुयी आराजी नम्बर 1175 अवस्थित है, जिस पर अपीलान्ट ने कुंआ व ट्युबबेल खुदवा रखा है व उक्त आराजी नम्बर 1175 का अपीलान्ट चाह के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व अपने खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 1175 जो चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड है व उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कुंआ व ट्युबबेल खुदा हुआ है, जिससे अपीलान्ट राजस्व भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ) कुंए खोदने व पम्प लगाने के लिए भूमि आवंटन ) नियम 1979 के नियम 12 क के अनुसार नियमन कराये जाने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य



नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, भदोसर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्त किस तरह से अतिक्रमी व मौके पर किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, कही स्पष्ट नहीं किया व छपे-छपाये फार्म पर खानापूरति कर निर्णय पारित कर दिया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, विवादित आराजीयात पर अपीलांत का पुराना कब्जा चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईशतुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

**91 Unauthorised occupation of Land** - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own



bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both : Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा



की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हत्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार भदेसर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांत स्वयं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांत राजस्व भू राजस्व (सिचाई प्रयोजनार्थ) कुंए खोदने व पम्प लगाने के लिए भूमि आंवटन ) नियम 1979 के नियम 12 क के अनुसार नियमन की पात्रता रखता है, अगर अपीलांत उक्त नियमों के संबंध में किसी भी प्रकार से पात्रता रखता है तो अपीलांत इस संबंध में सक्षम स्तर से चारागोही किये जाने के लिये स्वतंत्र है, किन्तु वर्तमान स्थिति में विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज अभिलिखित है ऐसी स्थिति में अपीलांत विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, भदेसर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)  
अतिरिक्त कलेक्टर,  
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

